

भारत - भूमध्यरेखीय गिनिया संबंध

भारत और भूमध्यरेखीय गिनिया के बीच भूमध्यरेखीय गिनिया के स्वतंत्र होने के पहले से ही (अर्थात् 1968 से पहले) सौहार्दपूर्ण एवं मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। भूमध्यरेखीय गिनिया पहले स्पेन का उपनिवेश था। दोनों देशों के बीच उच्च स्तर पर यात्राओं का कोई आदान प्रदान नहीं हुआ है, सिवाय इसके कि दोनों देशों के नेताओं ने यू एन, नाम आदि जैसे कुछ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मुलाकात की है। भारत द्वारा भूमध्यरेखीय गिनिया के साथ किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं किया गया है तथा कोई करार लंबित भी नहीं है। भूमध्यरेखीय गिनिया के साथ न तो कोई संयुक्त आयोग है और न ही कोई संयुक्त व्यापार समिति है।

राजनीतिक संबंध

अप्रैल 2004 में श्री ई बैरवा, तत्कालीन संयुक्त सचिव (पश्चिम अफ्रीका), एम ई ए ने मलाबो (भूमध्यरेखीय गिनिया) का दौरा किया तथा भूमध्यरेखीय गिनिया सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों एवं कुछ मंत्रियों के अलावा राष्ट्रपति से मुलाकात की। उस समय भूमध्यरेखीय गिनिया सरकार द्वारा टीम 9 करार पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर किए गए थे। पी ई सी लिमिटेड, नई दिल्ली और एंजिलिक इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली ने करार को कार्यान्वित करने में रुचि प्रदर्शित की। पी ई सी लिमिटेड टीम 9 पहल के तहत विभिन्न परियोजनाएं करने के लिए भूमध्यरेखीय गिनिया सरकार के साथ पहले से ही संपर्क में था। अक्टूबर 2007 में ओ वी एल ने तेल अन्वेषण के लिए बोली प्रस्तुत की तथा ई जी 12 और ई जी 13 ब्लाक के लिए मनपसंद बोलीदाता के रूप में उभरा। तथापि ओ वी एल को अंततः ब्लाक आवंटित नहीं किए गए। इसके अलावा ओ वी एल यू एस ए की देवोन एनर्जी के स्वामित्व वाले उत्पादन फील्ड में 20 प्रतिशत शेयर खरीदने का इच्छुक था। 2005 से 2008 तक भूमध्यरेखीय गिनिया की जिम्मेदारी समवर्ती रूप से नाइजीरिया में भारतीय उच्चायुक्त को सौंपी गई थी। 2008 में समवर्ती प्रत्यायोजन अंगोला में भारतीय दूतावास को शिफ्ट हो गया। मार्च 2008 में अपना प्रत्यय पत्र प्रस्तुत करते समय राजदूत ए आर घनश्याम ने भूमध्यरेखीय गिनिया के राष्ट्रपति के साथ तेल क्षेत्र में भारत - भूमध्यरेखीय गिनिया सहयोग के मुद्दे पर चर्चा की। ओ वी एल की रुचि से अवगत कराया गया। राष्ट्रपति ने कहा कि वह भारत को बहुत सम्मान की नजरों से देखते हैं तथा भारत का दौरा करने की अपनी इच्छा व्यक्त की। भूमध्यरेखीय गिनिया के विदेश मंत्री भी घनिष्ठ द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए भारत का दौरा करने के इच्छुक थे। उन्होंने अंग्रेजी भाषा में भूमध्यरेखीय गिनिया के 80 नागरिकों के प्रशिक्षण में भारत की सहायता के लिए अनुरोध किया। भूमध्यरेखीय गिनिया ने संयुक्त आयोग गठित करने तथा सामान्य सहयोग करार पर निर्णय लेने का प्रस्ताव किया।

जब भारत ने मई 2011 में आदिस अबाबा में दूसरी भारत - अफ्रीका मंच शिखर बैठक का आयोजन किया था तब बांजुल फार्मेट के अनुसरण में अध्यक्ष की हैसियत से भूमध्यरेखीय गिनिया की भागीदारी अपरिहार्य हो गई। इस सिलसिले में मई 2011 में राज्य मंत्री (आई टी एवं दूरसंचार) श्री सचिन पायलट ने प्रधानमंत्री के विशेष दूत के रूप में भूमध्यरेखीय गिनिया का दौरा किया। उन्होंने राष्ट्रपति टियोडोरो ओबियांग नगुयेमा मबासोगो से मुलाकात की और आदिस अबाबा में दूसरी भारत - अफ्रीका मंच शिखर बैठक में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री की ओर से निजी निमंत्रण सौंपा। श्री पायलट ने राष्ट्रपति के साथ क्षेत्रीय एवं वैश्विक मामलों की वर्तमान स्थिति पर भी चर्चा की तथा विदेश मंत्री पास्टोर मिका ओंडो बिले के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। भूमध्यरेखीय गिनिया के राष्ट्रपति अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष की अपनी हैसियत से आदिस अबाबा में दूसरी भारत - अफ्रीका मंच शिखर बैठक में भाग लिया।

जून 2011 में भूमध्यरेखीय गिनिया के राष्ट्रपति की अध्यक्षता में मलाबो में अफ्रीकी संघ (ए यू) की कार्यकारी परिषद की 19वीं सामान्य बैठक हुई। श्री राजेन्द्र भगत, तत्कालीन संयुक्त सचिव (पश्चिम अफ्रीका), एम ई ए के नेतृत्व में एक 4 सदस्यीय शिष्टमंडल ने इस बैठक में भाग लिया। भारत ने प्रेक्षक के रूप में शिखर बैठक में भाग लिया। अफ्रीकी संघ की कार्यकारी परिषद की 25वीं साधारण बैठक भी मलाबो में हुई। भारत ने एक

शिष्टमंडल के साथ इसमें प्रेक्षक के रूप में भाग लिया जिसमें श्री विनय कुमार, संयुक्त सचिव (ई एण्ड एस ए), एम ई ए; री संजय वर्मा, इथोपिया, जिबूटी में भारतीय राजदूत तथा अफ्रीकी संघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि शामिल थे।

आयुष राज्य मंत्री श्री श्रीपद येसो नाइक ने तीसरी भारत - अफ्रीका मंच शिखर बैठक के लिए निमंत्रण सौंपने के लिए प्रधानमंत्री के विशेष दूत के रूप में 24 और 25 अगस्त 2015 को भूमध्यरेखीय गिनिया का दौरा किया। उन्होंने राष्ट्रपति तथा विदेश मंत्री से मुलाकत की।

भूमध्यरेखीय गिनिया के राष्ट्रपति टियोडोरो ओबियांग नग्यूेमा मबासोगो ने तीसरी भारत - अफ्रीका मंच शिखर बैठक में भाग लेने के लिए अक्टूबर 2015 में पहली बार भारत का दौरा किया। उनके नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल ने इस शिखर बैठक में भाग लिया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि ब्रिक्स के सदस्य देश के रूप में भारत की सामरिक स्थिति को देखते हुए उनकी सरकार भारत - अफ्रीका सहयोग को खास महत्व देती है तथा बाधा मुक्त सहयोग स्थापित करना चाहती है ताकि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली के आर्थिक एवं वाणिज्यिक आदान प्रदान में सहूलियत हो। उन्होंने यह भी कहा कि भूमध्यरेखीय गिनिया अपनी अर्थव्यवस्था में विविधता लाने की प्रक्रिया में है और भूमध्यरेखीय गिनिया में निवेश के लिए मनपसंद क्षेत्रों का उल्लेख किया जिसमें ऊर्जा, मछली पकड़ना, वानिकी, पशुपालन, कृषि एवं खनन शामिल हैं। राष्ट्रपति एवं विदेश मंत्री ने अपने अपने भारतीय समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की।

अक्टूबर 2015 में भारत ने नई दिल्ली में एक रेजीडेंट मिशन खोलने के लिए अपने अनुमोदन के बारे में भूमध्यरेखीय गिनिया को अवगत कराया।

दूसरी भारत - अफ्रीका मंच शिखर बैठक की प्रक्रिया के तहत भारत ने भूमध्यरेखीय गिनिया में ग्रामीण विकास के लिए जियोइनफार्मेटिक अप्लीकेशन पर एक केन्द्र स्थापित करने की पेशकश की। अफ्रीका के भिन्न भिन्न लोकेशन में इस तरह के पांच केन्द्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव किए गए। जुलाई 2012 में भूमध्यरेखीय गिनिया के अधिकारियों ने इस परियोजना के लिए अपने सामान्य अनुमोदन से अवगत कराया।

आर्थिक एवं वाणिज्यिक संबंध

हालांकि भारत और भूमध्यरेखीय गिनिया के बीच आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध सीमित हैं, पिछले कुछ वर्षों में यह बढ़ रहा है, जिसका मुख्य कारण यह है कि भूमध्यरेखीय गिनिया तेल एवं अन्य ऊर्जा उत्पादों के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में उभर रहा है। द्विपक्षीय व्यापार जो वर्ष 2010-11 में 11.54 मिलियन अमरीकी डॉलर था, वर्ष 2014-15 में बढ़कर 764.39 मिलियन अमरीकी डॉलर हो गया है। भूमध्यरेखीय गिनिया विशेष रूप से फार्मास्युटिकल प्लांटों की स्थापना में भारतीय निवेश तथा आई टी क्षेत्र में सहयोग का इच्छुक है।

भूमध्यरेखीय गिनिया को भारत की ओर से निर्यात की जाने वाली मुख्य वस्तुओं में मछली एवं क्रस्टैसियंस, लोहा एवं इस्पात आदि शामिल हैं। भूमध्यरेखीय गिनिया से भारत जिन वस्तुओं का आयात करता है उनमें मुख्य रूप से कूड ऑयल एवं ऑयल डेरिवेटिव, सीड, औषधीय पौधे, अयस्क, स्लैब एवं ऐश, लकड़ी तथा लकड़ी की बनी वस्तुएं, प्राकृतिक या शोधित मोती, पत्थर, इमिटेशन ज्वैलरी आदि शामिल हैं।

पिछले पांच वर्षों के व्यापार के आंकड़े यहां नीचे दिए गए हैं :

(मिलियन अमरीकी
डालर में)

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
--	---------	---------	---------	---------	---------

भारतीय निर्यात	11.42	17.15	21.31	17.24	15.01
भारतीय आयात	0.12	206.02	524.83	301.82	749.38
कुल व्यापार	11.54	223.17	546.14	319.06	764.39

ऋण सहायता :

2005 में पेयजल परियोजना के लिए भारत के आयात - निर्यात बैंक द्वारा प्रदान की गई 5 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण सहायता को जून 2012 में निरस्त कर दिया क्योंकि भूमध्यरेखीय गिनिया के प्राधिकारी निर्धारित अवधि के अंदर संगत दस्तावेज तैयार करने और ऋण सहायता के तहत अपेक्षा के अनुसार अन्य औपचारिकताओं को पूरा करने में समर्थ नहीं हो पाए।

आई टी ई सी

आई टी ई सी कार्यक्रम के तहत भूमध्यरेखीय गिनिया को पांच स्लाट आवंटित किए गए हैं। तथापि भाषा संबंधी कठिनाइयों के अलावा भारत के साथ खराब कनेक्टिविटी के कारण भूमध्यरेखीय गिनिया सरकार से नामांकन प्राप्त करना बहुत कठिन है।

भारतीय समुदाय

लगभग 300 भारतीय नागरिक मलाबो के राजधानी शहर में डिपार्टमेंटल स्टोर एवं होटल आदि में काम कर रहे हैं। समय समय पर तेल कंपनियां आफशोर ऑयल इंस्टालेशन में भारतीय नागरिकों को अल्पावधिक आवंटन पर यहां लाती हैं।

उपयोगी संसाधन :

भारतीय दूतावास, लुआंडा की वेबसाइट :

<http://www.indembangola.org/>

भारतीय दूतावास, लुआंडा का फेसबुक पृष्ठ:

<https://www.facebook.com/pages/Embassy-of-India-Luanda/209463462473631>

जनवरी, 2016